

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग -1

देहरादून, दिनांक : 17 नवम्बर, 2015

विषय:-वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये प्रथम अनुपूरक अनुदानों की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल 2015 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक व धनराशियां आपके निवर्तन पर अग्रेत्तर स्वीकृतियां निर्गत करने हेतु रखी गयी थी। इसी क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 की प्रथम अनुपूरक मांगों एवं तत्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम-2015 पारित होने के फलस्वरूप प्रथम अनुपूरक मांग की धनराशियां निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन विभागों के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2- चूंकि अनुपूरक बजट में बजट प्राविधान मुख्यतः बचतों से वहन करने की परिकल्पना की गई है, अतः प्रथम अनुपूरक मांग की धनराशि व्यय हेतु निवर्तन पर रखने हेतु कड़े परीक्षण व नियंत्रण आधार पर ही कार्यवाही की जाय।

3- प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राविधानित धनराशि में वचनबद्ध मदों यथा वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते, मजदूरी, विद्युत देय, जलकर/जलप्रभार, औषधि, भोजन व्यय आदि व्ययों तथा अधिष्ठान सम्बन्धित अन्य मदों का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रशासनिक विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा वास्तविक आवश्यकता/व्यय का आकलन करते हुये एवं यथास्थिति मूल बजट के सापेक्ष धनराशि कम पड़ने की दशा में ही इन मदों की धनराशियां आहरण-वितरण अधिकारियों के निवर्तन में शासनादेश दिनांक 01.04.2015 में इंगित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत रखी जायें। आयोजनेत्तर/आयोजनागत पक्ष की राजस्व व्यय सम्बन्धी अन्य मदों के सापेक्ष भी वास्तविक आवश्यकता/व्यय का आकलन करते हुये मूल बजट की धनराशि कम पड़ने पर ही



मितव्ययता बरतने की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये वित्त विभाग के पूर्व परामर्श/सह-धनराशि आहरण—वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर रखी जायें।

4— चालू निर्माण वर्ष में मुख्य बजट एवं अनुपूरक बजट में प्राविधानित बजट के स अपलब्ध बचतों के आधार पर पूंजीगत मद से पूंजीगत मद में तथा राजस्व मद से राजस्व मद में पुर्निविनियोग के प्रस्तावों की वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धित अपर सचिव, वित्त के स्तर से जायेगी।

5— चालू निर्माण कार्यो एवं मानक मद-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता/अनुदान संख्या-35—पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान तथा मानकमद-42—अन्य व्यय (जिला योजना एवं केन्द्रीय पोषित योजनाओं को छोड़कर) के लिये आय-व्ययक के संबंधित मानक मद के अन्तर्गत प्राविधानित ₹ 2.00 करोड़ तक की धनराशि के प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग/बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा आहरण—वितरण अधिकारियों को दो चरणों में अपने स्तर से इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत की जायेगी कि नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार प्रथम किशत में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी एवं द्वितीय किशत को प्रथम किशत की उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही जारी किया जायेगा। चालू निर्माण कार्यो एवं मानक मद-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता/अनुदान संख्या-35— पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान तथा मानकमद-42—अन्य व्यय (जिला योजना एवं केन्द्रीय पोषित योजनाओं को छोड़कर) के लिये आय-व्ययक के संबंधित मानक मद के अन्तर्गत ₹ 2.00 करोड़ से ₹ 20 करोड़ की धनराशि के प्रस्ताव सम्बन्धित व्यय—नियंत्रण अनुभाग की सहमति से तथा ₹ 20.00 करोड़ से अधिक के प्रस्तावों पर राज्य की वित्तीय सुदृढता के दृष्टिगत सम्बन्धित व्यय—नियंत्रण अनुभाग के पश्चात् वित्त अनुभाग-1 की सहमति भी आवश्यक रूप से प्राप्त करते हुये तीन चरणों में निर्गत की जायेगी।

6— वर्ष 2015-16 के प्रथम अनुपूरक की केन्द्रपोषित/बाह्य सहायतित योजनाओं एवं एस0पी0ए0 अन्तर्गत भारत सरकार के स्तर पर अपलोडेड एवं अनुमत योजनाओं के सापेक्ष धनराशि मूल बजट की धनराशि कम पड़ने पर केन्द्र सरकार से धनराशि अवमुक्त हो जाने अथवा इस हेतु स्पष्ट अनुमोदन प्राप्त हो जाने की दशा में वित्त विभाग की पूर्व सहमति से आहरण—वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर व्यय हेतु रखी जायें।

7— एस0पी0ए0(आर0) के अन्तर्गत बजट प्राविधान आपदा विभाग के अन्तर्गत किया गया है। चूंकि यह एक समयबद्ध संसाधन (Time bound resource) है। अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा भारत सरकार की साईट पर अपलोडेड तथा स्वीकृत परियोजनायें एवं जिस पर



भारत सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है तथा धनराशि अवमुक्त भी कर दी गई है, ऐसे समस्त परियोजनाओं को भारत सरकार के द्वारा जारी धनराशि की सीमा तक वित्तीय स्वीकृति का अधिकार आपदा प्रबन्धन विभाग को दिया जाता है। आपदा प्रबन्धन विभाग धनराशि जारी करने से पूर्व वित्त अनुभाग-1 से यह सुनिश्चित कर लें कि सम्बन्धित परियोजनाओं पर धनराशि भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। किसी भी दशा में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त हुये बिना बजट अवमुक्त नहीं किया जायेगा।

8- इसके अतिरिक्त प्रथम अनुपूरक मांगों में विभिन्न घोषणाओं/एकमुश्त प्राविधान से सम्बन्धित योजनाओं का भी समावेश किया गया है। इस सम्बन्ध में धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सम्बन्धित सभी औपचारिकतायें यथा योजना/कार्य की नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है तथा डी०पी०आर०, टी०ए०सी०, ई०एफ०सी०, आदि आवश्यकतायें औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गई हैं। ऐसे प्रकरणों में भी प्रत्येक कार्य/प्रकरण के लिये धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व वित्त विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त किया जाय।

9. केन्द्रपोषित योजनाओं के सम्बन्ध में केन्द्रांश की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने पर प्रशासकीय विभाग अपने स्तर पर निर्गत कर सकते हैं। साथ ही यदि केन्द्रपोषित योजना 05.00 करोड़ से अधिक है तो प्र०वि० उसको दो किश्तों में निर्गत करेंगे। प्र०वि० द्वारा बजट निदेशालय से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त है, या नहीं तदपरान्त ही राज्यांश की धनराशि से सम्बन्धित प्रस्ताव योजनान्तर्गत केन्द्रांश के पूर्ण उपयोग के बाद ही वित्त विभाग को प्रस्तुत किये जायेंगे।

10. प्रथम अनुपूरक में जिन विभागों के राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु व्यवस्था की गयी है, वे तत्काल इसकी प्रतिपूर्ति उसी कोड से करें जिसमें राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि आहरित की गयी थी।

11. नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु धनराशि तीन चरणों में स्वीकृत की जायेगी। दूसरी किश्त प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही जारी की जायेगी। इसके अतिरिक्त कुल धनराशि उस सीमा तक अवमुक्त की जायेगी जो एच०पी०सी० (HPC) एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित होगी।

12. शासनादेश संख्या: 400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 की शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव, वित्त



संख्या 1336 (1)/XXVII(1)/2015 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4. समस्त जिला वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. शासन के समस्त अनुभाग।
- ✓ 6. एन0 आई0 सी0, सचिवालय, देहरादून।
7. उपनिदेशक, शासकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस आदेश की 500 प्रतियाँ कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव, वित्त